<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

02 अगस्त, 2017

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निम्नलिखित बयान जारी किया :–

<u>''देश की जनता पर भाजपा का तिहरा प्रहार – रसोई गैस व पेट्रोल–डीजल के दामों में बढोत्तरी और बचत की ब्याजदर में कटौती''</u>

<u>''मोदी सरकार का जनविरोधी चेहरा बेनकाब – आम आदमी की जेब पर डाका डाल खजाना भरने की कवायद''</u>

प्रजातंत्र का मूल उद्देश्य तो है, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिक को सहायता पहुंचाना। मगर भाजपा सरकार मुट्ठीभर अमीरों को लाभ पहुंचा उसका बोझ आम नागरिक पर डाल रही है।

केंद्र की भाजपा सरकार ने आज देश के 60 करोड़ से अधिक लोगों पर तिहरा आर्थिक प्रहार किया है। रसोई गैस व पेट्रोल–डीज़ल के दाम बढ़ाने की कवायद तथा बचत पर ब्याज की कटौती ने भाजपा का आम जनमानस विरोधी चेहरा बेनकाब कर दिया है। सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी व भाजपा आए दिन ताबड़–तोड़ टैक्स लगाकर देश की जनता की कमर तोड़ने पर उतारू हैं।

एक तरफ तो पूरा देश पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और व्यापक आर्थिक मंदी की मार से ग्रस्त है, तो दूसरी तरफ सरकार साधारण जनमानस की जेब से उसकी गाढ़ी कमाई का पैसा नए नए टैक्स लगाकर रोज रोज निकाल रही है। व्यापक आर्थिक मंदी, चौपट होते हुए धंधों, बेतहाशा बेरोजगारी व टैक्सों की सीनाजोरी ने जनता का जीना दूभर कर दिया है। मोदी सरकार के ताजा फैसलों ने तो देश की जनता पर एक ऐसी तिहरी मार मारी है, जिससे हर घर का बजट संकट में पड़ जाएगा।

<u>रसोई गैस की आसमान छूती कीमतें – गृहणियों द्वारा हाहाकार</u>

देश के 18.11 करोड़ उपभोक्ता परिवार सब्सिडाईज़्ड रसोई गैस सिलेंडर आए माह खरीदते हैं। एक तुगलकी फरमान जारी कर मोदी सरकार ने 1 जुलाई, 2017 से आए माह 4 रु. प्रति सिलेंडर मार्च 2018 या उसके बाद तक बढ़ाकर गैस सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया है, यानि कि सिलेंडर की कीमतें मौजूदा 479 रु. प्रति सिलेंडर से बढ़कर 524 रु. प्रति सिलेंडर हो जाएंगी, जो कि नॉन सब्सिडाईज़्ड सिलेंडर का आज का रेट है। पिछले तीन साल में मोदी सरकार पहले ही सब्सिडाईज़्ड गैस सिलेंडर के भाव 66 रु. बढ़ा चुकी (मई 2014 में 414 रु. प्रति सिलेंडर से बढ़कर आज के दिन 479 रु. प्रति सिलेंडर तक)। इस प्रकार से कुल 110 रु. प्रति सिलेंडर की यह वृद्धि न केवल गृहणियों का बजट बिगाड़ेगी, परंतु जनता की कमर तोड़ देगी।

तीन साल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में 35 प्रतिशत कमी आई, परंतु इसके बावजूद भाजपा सरकार जनता की जेब काट मुनाफाखोरी कर रही है। इसके विपरीत

यूपीए–कांग्रेस सरकार 10 वर्षों तक प्रति सिलेंडर 449 रु. की सब्सिडी आम जनमानस को देती थी। यही दोनों दलों की सोच और रास्ते में अंतर है।

SBI द्वारा बचत खाते के ब्याज में 4 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत की कटौती – 37 करोड़ खाताधारकों को लगभग 4700 करोड़ का नुकसान

भारत सरकार के मुख्य बैंक, SBI द्वारा 31 जुलाई, 2017 से बचत खाते की ब्याज दर 4 प्रतिशत से घटाकर 3.5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। SBI के बचत खातों में लगभग 37 करोड़ लोगों का 9.4 लाख करोड़ जमा है। यदि आधा प्रतिशत ब्याज की कटौती हो तो सीधे सीधे 4700 करोड़ सालाना का नुकसान आम जनमानस को होगा।

इससे पहले भी मौजूदा सरकार ने 1 अप्रैल, 2017 से 3 बार से अधिक बैंक खातों के लेन–देन पर 100 रु. टैक्स व ATM से पैसा निकालने पर टैक्स लगा दिया। इसके साथ साथ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि खातों, किसान विकास पत्र व पब्लिक प्रॉविडेंट फंड पर भी ब्याज की दरें कम कर जनता पर सीधे प्रहार किया था।

पेट्रोल–डीज़ल के दाम फिर बढ़ाए– 12000 करोड़ सालाना का अतिरिक्त बोझ।

एक बार फिर, 01 अगस्त, 2017 से पेट्रोल पर डीलर कमीशन को 1 रु. प्रति लीटर तथा डीज़ल पर 72 पै. प्रति लीटर बढ़ाने की कवायद है, जिसका सीधा बोझ भाजपा सरकार न वहन कर जनता पर लाद रही है। इस बढ़ोत्तरी से आम जनमानस पर 12000 करोड़ रु. का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पिछले तीन सालों यानि मई 2014 से आज तक कच्चे तेल की कीमतें 53 प्रतिशत गिरी हैं। अगर इसका फायदा देश की जनता को दिया जाता, तो पेट्रोल की कीमतें 37.84 रु. प्रति लीटर व डीज़ल की कीमतें 29.40 रु. प्रति लीटर होतीं। सच्चाई यह है कि भारत सरकार पेट्रोल–डीज़ल पर टैक्स व आयात शुल्क लगाकर 2,33,000 करोड़ सालाना कमा रही है। यह नया फैसला जनता को और उत्पीड़ित करेगा।

देश के 125 करोड़ लोग पुकार पुकार कर कह रहे हैं –

''टैक्सों की भरमार,

जनता करे हाहाकार,

ऐसी रही मोदी सरकार।''